



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 18 मार्च, 2002/27 फाल्गुन, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय प्रादेश

कुल्लू, 28 फरवरी, 2002

संख्या पी०सी०एच० (कु०) ग्रा० पं० कार्ड्स-332-36. —यह कि श्री खेख राम उप-प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत कार्ड्स, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को मामला प्राथमिकी सूचना संख्या 167/2001, दिनांक 7-4-2001 को भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 व 42 भारतीय दण्ड संहिता 379 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था। जिसके अन्तर्गत उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (1) पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम; 1997 के नियम 142 में प्रदत्त शक्तियों द्वारा उक्त उप-प्रधान को इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या पी०सी०एच० (कु०) ग्राम पंचायत कार्ड्स 996-1001, दिनांक 19-5-2001 को निलम्बित किया गया है।

अवर सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच०ए० (5) 7/2001-2261, दिनांक 14 फरवरी, 2002 के अन्तर्गत श्री खेख राम, उप-प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत कार्ड्स, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के निलम्बन आदेश को विधि विभाग द्वारा परीक्षण करने उद्देश्य से अवध ठहराया है।

अतः मैं, आर० डी० नजीम, उपायुक्त कुल्लू, हिमाचल प्रदेश इस कार्यालय के आदेश संख्या पी०सी०एच० (कु०) ग्राम पंचायत कार्ड्स-996-1001, दिनांक 19-5-2001 को वापिस लेकर नत्काल प्रभाव में रद्द करता हूँ।

आर० डी० नजीम,

उपायुक्त,

कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

## कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)

## कार्यालय आदेश

मण्डी, 7 मार्च, 2002

संख्या पी०सी०एस०-एम०एन०डी०-2001-965-74.—यतः श्रीमती गौरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या पी०सी०एम०-एम०एन०डी० 2001-119-23, दिनांक 8-1-2002 द्वारा 15 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे। क्योंकि न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा-122 (VI) के अन्तर्गत प्रधान पद पर पदासीन रहने के आयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए।

तथा यह कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त पंचायत अधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त न होने पर उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक संख्या 526, दिनांक 13 फरवरी, 2001 द्वारा पुनः अवसर दिया गया कि वे कारण बताओ नोटिस में वर्णित सन्दर्भ में अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें। स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि श्रीमती गौरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ में पत्रोत्तर द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए यह तर्क दिया है कि क्योंकि वह 8 जून 2001 जब कि पंचायत पदाधिकारियों पर दो से अधिक सन्तान उत्पन्न करने पर आयोग्यता का प्रावधान लागू हुआ है, उसे पहले से ही वह गर्भवती थी। अतः वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122(61) के अन्तर्गत वर्णित आयोग्यता के अन्तर्गत नहीं आती है।

औ यह कि पंचायत पदाधिकारी के उक्त स्पष्टीकरण की हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम व इसका अधीन बनाए गए नियमों के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच किए जाने पर इसे असन्तोषजनक पाया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 में संशोधन वास्तव में 8 जून, 2000 को लाया जा चुका था। जिसके अनुसार पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 के साथ खण्ड (61) जोड़ा गया था। अर्थात् पंचायत पदाधिकारियों के दो सन्तान से अधिक सन्तान होने पर आयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया, परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून, 2001 तक दी गई थी। इस प्रकार वर्णित प्रावधान के प्रभाव में प्रत्येक पंचायती राज पदाधिकारी जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात् दो सन्तान से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हैं।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्रीमती गौरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर का प्रधान पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जगदीश चन्द्र शर्मा (भा० प्र० से०), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122(1) के खण्ड (VI) व 122(2) के अधीन प्राप्त हैं, श्रीमती गौरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को तत्काल प्रधान पद पर आसीन रहने के आयोग्य घोषित करता हूँ तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा-131(1) व (2) के प्रावधान के अनुपालन में ग्राम पंचायत सरोआ, विकास खण्ड गोहर, के प्रधान पद का रिक्त घोषित करता हूँ।

जगदीश चन्द्र शर्मा,  
उपायुक्त,  
मण्डी, जिला मण्डी।